the Indian market succeeds it will have to be essentially at the cost of indigenous manufactures and designers like C-DOT, ITI etc. ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (d) Market share of various companies for different telecom equipments and services varies according to the items, policies and procedures followed by each country.

The price offered by any company depends upon the technical specifications and configurations of the equipment.

Department of Telecommunications purchases telecom equipment from the companies registered in India based on open tenders, on rupee payment.

(e) and (f) Do not arise.

Licences for Local Radio Loops

1922. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRIMATI SARALA MAHESHWARI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether licences are proposed to be given to Operators for Local Radio Loops for providing basic telecom services; and

(b) if so, what will be the effect of such a move on the tariff structure?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) National Telecom. Policy guidelines permit licensing of one private service operator per Telecom. Circle to operate the basic telecom. services in addition to D.O.T. Local Radio loops technology, which is of recent origin could be one of the available options.

(b) The effect of such a move on tariff structure can be assessed only when the manufacturing base for such technology stabilizes which is not the case at present.

C-DOT Switches

1923. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Germans have a national switch in the siemens, the Japanese have in the NEC and Fujitsu, the Swedes have in Ericsson and the French in Alcatel;

(b) if so, whether Government are considering to evolve the C-DOT switches as the national switch for the country given the impressive record of these switches in the divers and different Indian terrain particularly the rural areas:

(c) if so, what sort of support Government envisage for extending that to the Research and Development efforts in C-DOT; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Government is not aware of any classification as a national switch by Germans, Japanese, Swedes and the French.

(d) Does not arise in view of 'c' above. ed widely in the country's network.

(c) Government extends full support to R&D efforts of C-DOT.

(d) Does not arise in view of 'c' above.

वालिया तालुका स्थित डाकघर में पोस्ट कार्डों की कमी

1924. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी गुजरात में विशेष रूप से वालिया तालुका स्थित डाकघर में पोस्टकार्ड उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अक्तूबर, 1994 तक उक्त डाकघर को कुल कितने पोस्टकार्ड उपलब्ध कराये गये थे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जनवरी, 1994 से अक्तूबर, 1994 तक विभाग द्वारा उक्त डाकघर को 54,000 पोस्टकार्ड उपलब्ध कराई किए गए थे ।

अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन

1925. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों हेतु एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने का कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में लगाये गए ऐसे टेलीफोनों की जिलावार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) प्रत्येक जिले के लिए अगामी वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति के अंतर्गत वर्ष

1997 तक देश के सभी ग्रामों में टेलीफोन और शहरी क्षेत्रों में जिसमें जनजातिय क्षेत्र भी शामिल हैं, प्रत्येक 500 की आबादी पर एक पी० सी० ओ० खोलने का प्रस्ताव है ।

जिला और पंचायत स्तर पर टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

1926. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला और पंचायत स्तरों पर टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं । प्रत्येक दूरसंचार सर्किल के लिए दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में तथा प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन जिला प्रबंधक/महाप्रबंधक की अध्यक्षता में किया जाता है ।

(ख) उक्त उल्लिखित गठित, पुनर्गठित दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । **(नीचे देखिए)** ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

गठित दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों की सूची

1. **आंध्र प्रदेश :**
   - आंध्र प्रदेश राज्य
   - ईलूरू
   - गुन्टाकल
   - गुन्टूर
   - हैदराबाद
   - कुरनूल
   - राजमुन्द्री
   - विजयवाडा
   - विशाखापटनम
   - तिरूपति
2. **अरुणाचल प्रदेश :**
   - अरुणाचल प्रदेश राज्य
3. **असम :**
   - असम राज्य
   - गुवाहाटी
4. **बिहार :**
   - बिहार राज्य
   - रांची
5. **गोवा :**
   - गोवा राज्य
6. **गुजरात :**
   - गुजरात राज्य
   - भुज
   - बुलसर (बल्साड)
7. **हरियाणा :**
   - हरियाणा राज्य
   - अम्बाला
   - फरीदाबाद
   - करनाल
   - रोहतक
   - हिसार
8. **हिमाचल प्रदेश :**
   - हिमाचल प्रदेश राज्य
9. **जम्मू एवं कश्मीर :**
   - जम्मू एवं कश्मीर राज्य
   - श्रीनगर
   - जम्मू
10. **कर्नाटक :**
    - कर्नाटक
    - हुबली
    - मैसूर
    - बेलगाम
    - मंगलौर
    - बैंगलूर
    - कोडागू
11. **केरल :**
    - केरल
    - अल्लेप्पी
    - क्विलॉन
    - कोट्टायम
    - कैन्नूर
    - पालघाट
    - एर्नाकुलम
    - त्रिचूर
12. **मध्य प्रदेश :**
    - मध्य प्रदेश
    - भोपाल
    - रायपुर